: आयुक्त (अपील-।) का कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, आंबावादी अहमदाबाद— 380015.

	सैन्टल एक्सोइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, आंबावाडी, अहमदाबाद— 380015.
क	सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पीलिटैक्नीक के पास, आंबावाडी, अहमदाबाद— 380015. फाइल संख्या : File No : V2(GTA)51/STC-III/2016/Appeal-I अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-092-16-17
ख	अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: <u>AHM-EXCUS-003-APP-092-16-17</u> दिनाँक Date <u>07.09.2016</u> जारी करने की तारीख Date of Issue
	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव . आयुक्त (अपील-l) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अहमदाबाद द्वारा प्रारित
	Passed by Shri Abhai Kumar Srivastav Commissioner (Appeals-I) Central Excise Ahmedabad
ग	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश स से सृजित
ध	Arising out of Order-in-Original No <u>GNR-STX-DEM-DC-51/2015</u> dated : <u>23.10.2015</u> Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Mehsana, A'bad-III. <u>अपीलकर्ता /</u> प्रतिवादी का नाम एवं पता Name & Address of The <u>Appellants</u> /Respondents
	M/s. Jay Somanth Transport Co.

इस अपील आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उचित प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित प्रकार से कर

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :-

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील:--Appeal to Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :-

वित्तीय अधिनियम,1994 की धारा 86 के अंतर्गत अपील को निम्न के पास की जा सकती:— Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :-

पश्चिम क्षेत्रीय पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ.20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेधाणी नगर, अहमदाबाद-380016

The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad – 380 016.

- अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के वित्तीय न्यायाधिकरण को (ii) सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9(1)के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी— 5 में चार अपील प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस स्थान में न्यायाधिकरण का न्यायपीठ स्थित है, वहाँ के नामित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी।
- The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated.



- (iii) वित्तीय अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप—धारा (2ए) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (2ए) के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी.7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आदेश की प्रतियाँ (उसमें से प्रमाणित प्रति होगी) और आयुक्त / सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन करने के निदेश देते हुए सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड / आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रति भेजनी होगी।
- (iii) The appeal under sub section and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 & (2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Central Board of Excise & Customs / Commissioner or Dy. Commissioner of Central Excise to apply to the Appellate Tribunal.
- 2. यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975 की शर्तो पर अनुसूची—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन प्राधिकारी के आदेश की प्रति पर रू 6.50/— पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।
- 2. One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjuration authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- 3. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1982 में चर्चित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।
- 3. Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- 4. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनांक: ०६.०८.२०१४ जो की वित्तीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- → आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगे।
 - 4. For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.
- → Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (4)(i) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भ्गतान पर की जा सकती है।



ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been filed by M/s. Jay Somnath Transport Co. Mehsana (hereinafter referred to as 'the appellant) against the Order-in-Original GNR-STX-DEM-DC-51/2015 dated 23.10.2015 ('the impugned order') passed by the Deputy Commissioner, Central Excise & Service Tax, Division-Gandhinagar, Ahmedabad-III ('the adjudicating authority').

- The facts in brief are that the appellant is engaged in supply of tankers to M/s Oil and Natural Gas Corporation Limited (for short-ONGC) under a contract/ agreement for interlocation transportation of brine/ crude oil/ effluent/ emulsion/ mud/ operational water etc. of ONGC, Mehsana Asset on the basis of fixed monthly charges. ONGC has paid service tax on 25% of such hiring charges by availing abatement under "Goods Transport Agency" service. As it appeared that with effect from 16.05.2008, the service provided by the appellant got covered under the "Supply of Tangible Goods" Service, a case was booked against the appellant by the Directorate General of Central Excise Intelligence Unit (DGCEI). Show Cause Notices were issued by the DGCEI and jurisdictional Central Excise Officer to the appellant for non-payment of service tax under the service category of "Supply of Tangible Goods" for the period from 16.05.2008 to 31.03.2013, which was confirmed/ upheld by the adjudicating authority/appellate authority. The present case pertains to the period from April 2013 to March 2014; A demand notice dated 01.04.2015 for short payment of Rs. 1,93,020/with interest leviable and imposition of penalty was issued. The said impugned notice was adjudicated vide the impugned order, by confirming the short paid amount with interest and imposition of penalty under Sections 78, 77(1)(a) and 77(2) of the Finance Act, 1994.
 - Being aggrieved, the appellant has filed the present appeal on the grounds that they 3. were providing GTA service and tax was correctly paid by the ONGC under GTA category; that they were providing GTA service to ONGC before introduction of 'supply of tangible goods service' and the department had accepted the same for the earlier period; that there was no change in the nature of service / requirement as per agreement after the introduction of the said new service; that in the present case both consignor and the consignee were ONGC and all aspects were monitored by ONGC; that though the convey note was prepared by ONGC, the same was signed by the driver on behalf of the appellant, which made the document a legally enforceable document and on par with lorry receipt/consignment note; that as the tax liability was correctly paid by ONGC, the same cannot be subjected to tax again in the hands of appellant under a different category; that there are two conditions to be satisfied for classifying the service under supply of tangible goods- first is right of possession of goods should not be transferred and second effective control of goods should not be transferred; that in the instant case although right of possession of oil tankers was not transferred, yet effective control of tankers were transferred to ONGC. It is further contended that non-payment of VAT cannot be a ground for confirming the demand under supply of tanging goods service;

that penalty under Section 78 cannot be imposed without any willful suppression of facts or intention to evade payment of service tax; that the issue is arising out of interpretation of the provisions of law; that Section 77 and Section 78 are all subject to Section 80 of the Finance Act, 1994. The appellant has cited various case laws in support of their submissions.

- 4. Personal hearing in the matter was held on 11.08.2016. Shri Arpan Yagnik, Chartered Accountant appeared on behalf of the appellant. He reiterated the submissions advanced in the grounds of appeals.
- I have carefully gone through the case records and submission made by the appellant. The issue to be decided in the matter is as to whether the service rendered by the appellant is classifiable under the service "Supply of Tangible Goods" as per provisions of Section 65 (105) (zzzzj) of the Finance Act, 1994, or under "Goods Transport Agency" service as defined under Section 65(105)(zzp) of the Finance Act, 1994.
- 6. Section 65 (105) (zzzzj) of the Finance Act, 1994 defines "Supply of Tangible Goods" Services", as follows:

"Taxable service means" any service provided or to be provided to any person, by any other person in relation to supply of tangible goods including machinery, equipment and appliances for use, without transferring right of possession and effective control of such machinery, equipment and appliances."

Section 65(105)(zzp) of the Act, *ibid*, defines taxable service under "Goods Transport Agency, as follows:

"taxable service means" any service provided or to be provided to any person, by a goods transport agency, in relation to transport of goods by road in a goods carriage;

Section 65(50b) of the Finance Act, 1994 defines Goods Transport Agency Service, as a follows:

"Goods Transport Agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called."

The adjudicating authority has classified the service rendered by the appellant under "Supply of Tangible Goods". I observe that the entry No.(zzzzp) of Section 65 (105) of the Act *ibid* referred above is a new entry inserted vide Finance Act 2008 with effect from 16.05.2008. To fall within the definition of taxable service of "Supply of Tangible Goods" referred above, mainly two conditions are required to be satisfied - (i) there should be a supply of tangible goods for use; (ii) there should not be any transfer of right of possession and effective control of such goods. Once these two conditions are satisfied, the provisions of the said entry will be attracted. To fall within the statute viz. Section 65(50b), which defines the "Good Transport Agency" and taxability on such service under clause of Section 65(105)(zzp) of the Act *ibid*, there should be a service in relation to transport of goods by road coupled with issue of consignment notes.

- 8. In the instant case, I observe that the appellant used to supply tankers to ONGC for use in inter-location transportation of various goods of ONGC, on the basis of monthly fixed charges under a contract/agreement. Relevant excerpts from the contract signed between the appellant and ONGC are reproduced below for ease of reference:
 - 1) The services under the contract were to perform carriage of Crude oil/ hot oil/emulsion/ effluent/ operational water/ brine/mud etc. technical water etc. from installation or vice versa and for any other purpose for transportation and may also require to perform outstation duties.
 - 2) M/s. Jay Somnath Transport Co. (Contractor) shall provide specified number of Tankers with driver and helper under the contract, hired by ONGC on dedicated monthly basis.
- From the terms of the agreement entered into between the appellant and ONGC, it is 9. clear that the service provided by the appellant is essentially supply of tankers along with its personnel, to operate the same on charter hire basis for use by ONGC and the payment for the services rendered is made on monthly basis to the appellant. In the present case, the appellant has supplied tankers along with drivers and helpers. In the circumstances, it is the appellant, who has possession and effective control over the tankers, by virtue of appellant supplying the drivers and helpers with tankers. The drivers and helpers supplied are the employees of the appellant and not of ONGC. Further, the contract clearly shows that there is no transfer of right of possession by the appellant to M/s. ONGC. The above contract also indicates the fact that the appellant is technically bound by ONGC, in terms of the compatibilities of tankers and the competence of the manpower engaged with such tankers, inasmuch as the appellant should provide specified number of tankers with competent driver and helpers with up to date vehicle documents and required equipments viz., spare wheel and tools etc. In respect of manpower associated with the tankers in question supplied by the appellant, it is presumed " that the salaries/wages are to be paid by the appellant, they being the employer. Looking into the circumstances of this case, I observe that the owner of the tanker is the appellant, who supplied the said tanker to ONGC for use in transportation of various goods by ONGC and raised bills on monthly basis for hired tankers, owned by them.
- 10. Vide Finance Bill, 2008, service provided in relation of "Supply of Tangible Goods", without transferring right of possession and effective control of the said tangible goods are specifically included in the list of taxable service. A brief description was given in para 4.4 of Board's letter D.O.F No.334/1/2008-TRU dated 29.02.2008 which reads as under:

"4.4.1 Transfer of the right to use any goods is leviable to sales tax / VAT as deemed sale of goods [Article 366(29A)(d) of the Constitution of India]. Transfer of right to use involves transfer of both possession and control of the goods to the user of the goods.

4.4.2 Excavators, wheel loaders, dump trucks, crawler carriers, compaction equipment, cranes, etc., offshore construction vessels & barges, geo-technical vessels, tug and barge flotillas, rigs and high value machineries are supplied for use, with no legal right of possession and effective control. Transaction of allowing another person to use the goods, without giving legal right of possession and effective control, not being treated as sale of goods, is treated as service.

अहमदाबार

4.4.3 Proposal is to levy service tax onsuch services provided in relation to supply of tangible goods, including machinery, equipment and appliances, for use, with no legal right of possession or effective control. Supply of tangible goods for use and leviable to VAT / sales tax as deemed sale of goods, is not covered under the scope of the proposed service. Whether a transaction involves transfer of possession and control is a question of facts and is to be decided based on the terms of the contract and other material facts. This could be ascertainable from the fact whether or not VAT is payable or paid."

- The appellant argued that non-payment of VAT cannot be a ground for confirming the demand under supply of tangible goods service. Payment of VAT on a transaction indicates that the said transaction is treated as sale, i.e. transfer of right to possess. In the instant case, ownership and control of the goods i.e. tankers remained with the appellant and only monthly hire charges were raised. Had there been transfer of possession, i.e. sale, then VAT would have been paid, which is not the case. The activities of transportation of various goods i.e. assets of ONGC were carried out by ONGC only. Thus, it is clear that the appellant was supplying goods i.e. tankers to ONGC. Thus, it is clear that the appellant was supplying goods i.e tankers to ONGC. Thus, it is observed that the service under consideration was covered within the ambit of "Supply of Tangible Goods" service, as elaborated under paras 4.4.1 to 4.4.3 of TRU letter dated 29.02.2008.
- 12. Further, the essence of the contract made between the appellant and ONGC is for 'supply' of tankers for transportation of goods by ONGC, who themselves are both the consignor and consignee of goods. The appellant has argued that though the convey note was prepared by ONGC, the same was signed by the driver on behalf of the appellant, which made the document a legally enforceable document and thus on par with lorry receipt/consignment note. The above argument is not acceptable, going by the explanation regarding consignment note mentioned under Rule 4B of Service Tax Rules, 2004, which is reproduced as follows for ease of reference:

'4B Issue of consignment note. - Any goods transport agency which provides service in relation to transport of goods by road in a goods carriage shall issue a consignment note to the customer:

Provided that where any taxable service in relation to transport of goods by road in a goods carriage is wholly exempted under section 93 of the Act, the goods transport agency shall not be required to issue the consignment note.

Marie

Explanation - For the purposes of this rule and the second proviso to rule 4A, "consignment note" means a document, issued by a goods transport agency against the receipt of goods for the purpose of transport of goods by road in a goods carriage, which is serially numbered, and contains the name of the consignor and consignee, registration number of the goods carriage in which the goods are transported, details of the goods transported, details of the place of origin and destination, person liable for paying service tax whether consignor, consignee or the goods transport agency.'

As per the above referred definition, consignment note should be issued by a goods transport agency against the receipt of goods for the purpose of transport of goods by road in a goods carriage, which is serially numbered; and it should contain the name of the consignor and consignee, details of vehicle registration, goods transported, place to be a light destination and details regarding payment of service tax. Further, it has been made than details regarding payment of service tax.

अहमदाबाद

7

for every GTA to issue consignment note to the receiver of service under the said rule. Generally, when a person deposits the goods with any transporter for the purpose of transport to a given destination, the transporter issues the lorry receipt or consignment note to the person depositing the goods. The name of the consignee is mentioned on such note. The original copy of the lorry receipt is sent by the person depositing the goods i.e. consignor to the consignee to enable him to collect the goods from the transporter.

- 14. In the instant case, the appellant has supplied tanker to ONGC and ONGC carried out the activities by using the said tanker as per their requirement of transporting goods owned by them. Therefore, both consignor and consignee is ONGC. Thus, the appellant only supplied tanker and manpower to ONGC in the capacity of a tanker owner and not in the capacity of a "Goods Transport Agency". Further, they did not issue any consignment note for the transportation of such goods. In fact, the appellant was only raising the bills on monthly basis for hire of tankers, owned by them for supply of tankers to ONGC for their highly "specified usage. Further, the convey notes as mentioned by the appellant cannot be termed as consignment notes as they do not conform to the conditions mentioned in explanation above for being construed as a consignment note, and the same were prepared by ONGC only for their record. Drivers used to merely sign it in token of having received the direction by ONGC. It is noted that there was no reference to convey note in the contract, clearly indicating that it was an internal affair of ONGC, and had nothing to do with the appellant.
- 15. The appellant has argued that it is an accepted fact that prior to the introduction of the service of "supply of tangible goods", they were providing the same nature of service and were paying service tax under GTA service; that there has been no change in nature of service and requirement, as per agreement after the introduction of the said service "supply of tangible goods"; that therefore service tax cannot be charged under different service. This argument is not tenable for the following reasons.
- Provisions about the classification of services are provided under Section 65A of the Finance Act. The said section is as under:-

65A. Classification of taxable services. -

- (1) For the purposes of this chapter, classification of taxable services shall be determined according to the terms of the sub-clauses (105) of Section 65;
- (2) When for any reason, a taxable service is prima facie, classifiable under two or more sub-clauses of clause (105) of Section 65, classification shall be effected as follows:-
- (a) the sub-clause which provides the most specific description shall be preferred to sub-clauses providing a more general description;
- (b) Composite services consisting of a combination of different services which cannot be classified in the manner specified in clause (a), shall be classified as if they consisted of a service which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable;
- (c) when a service cannot be classified in the manner specified in clause (a) or clause (b), it shall be classified under the sub-clause which occurs first the sub-clauses which equally merits consideration;

- On going through the various services before the introduction of negative list concept (which has done away with positive list), it would be seen that there is no pattern or mutual exclusivity in the scope of various services. In Customs and Central Excise Tariff the classification of the goods is based on highly scientific pattern. In case of Service Tax, however, various services were brought into the tax net from 1994 onwards on *ad hoc* basis. There is no pattern in the order the services were brought under the tax net. Descriptions of the services are not mutually exclusive. Some of the services are very specific and precise while some are wide in scope. This is the reason that recourse needs to be taken to Section 65A for classifying particular services at a particular point of time. As per Section 65A of the Finance Act, if a service is classifiable under two or more sub-clauses of clause (105) of Section 65, Classification shall be effected to the sub-clause which provides the most specific description to sub-clauses providing a more general description. From the above definitions, I find that the activity under consideration is more specifically covered under the category "Supply of tangible goods service".
- In the case of Commissioner of Central Excise. Agra V/s M/s Agra Computers, reported at 2014(34)STR 104 (Del-Tri), it has been held that Section 65A of Finance Act, provides guidance for determination of classification of taxable services for classification to be determined in terms of sub-clauses of Section *ibid*. Relevant para is as under:
 - "11. Section 65A was incorporated into the Act by the Finance Act, 2002 with effect from 14-5-2003, to provide guidance for determination of classification of taxable services. Clause (1) of this provision provides that classification of taxable services shall be determined according to the terms of the sub-clauses of Section 65(105). Clause (2) provides that if for any reason, a taxable service is, prima facie, classifiable under two or more sub-clauses of Section 65(105), classification shall be effected according to the norms set out in sub-clauses (a) to (c) of Section 65A. Sub-clause (a) provides that the sub-clause of Section 65(105) which provides the most specific description shall be preferred to sub-clauses providing a more general description. Sub-clause (b) states that composite services consisting of a combination of different services which cannot be classified in the manner specified in clause (a), shall be classified as if consisting of a service which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable. Sub-clause (c) is in the nature a residual guidance for classification and is to be resorted to when a service cannot be classified in the manner specified in clauses (a) or (b), and provides that it should be classified under that sub-clause of Section 65(105) which occurs first among the sub-clauses which equally merit consideration."
- Developers (P) Ltd reported at 2015 (39) STR 455, held that "The classification of a service must always be on analysis of the characteristics of the service, analyzed in terms of the provisions of the Act; considered in the light of the guidance provided in Section 65A of the Act; and identification of which of the clauses of Section 65(105), the service in issue falls into". In the case of M/s Premier Prest Control (P) Ltd, reported at 2015938) STR 870, the Hon'ble Tribunal Delhi has also held that classification of service is to be determined with respect to nature thereof vis-à-vis definitions of various services given in Section 65, read with Section 65A of Finance Act, 1994.

अहमदाबार

- 16.5. With effect from 16.05.2008, Section 65(105)(zzzzj) defines as taxable service, including to any person, by any other person in relation to supply of tangible goods including machinery, equipment and appliances for use, without transferring right of possession and effective control of such machinery, equipment and appliances. Looking into the activities of the appellant this i.e 65(105)(zzzzj) is a more specific entry than Section 65 (50b) read with Section 65(105)(zzp) of Finance Act, 1994.
- 17. I observe that the Hon'ble Tribunal, Mumbai in the case of M/s Greatship (I) Ltd reported at 2015 (37) STR 544 (Tri-Mumbai) decided a similar issue. In the said judgment, the Hon'ble Tribunal held that the activity of supply of drilling rig along with its personnel to operate the same on charter hire basis without transferring possession and active control comes within the ambit of "supply of tangible goods". The relevant excerpts are reproduced below for ease of reference:
 - "3 Thus, from the terms of the agreement entered into between the appellant and M/s. ONGC, it is clear that the service provided by the appellant is essentially supply of drilling rig along with its personnel to operate the same on charter hire basis and the payment for the services rendered is made on per-day basis. Thus, from the terms of the contract, it is clear that the activity comes within the scope of 'supply of tangible goods for use'. In the present case, the appellant has supplied drilling rigs along with the crew. Thus it is the appellant who has possession and effective control over the drilling rig. The crew so supplied are the employees of the appellant and not of ONGC. Consideration is paid on per-day basis. All these elements in the contract clearly show that there is no transfer of right of possession and effective control by the appellant to M/s. ONGC."

(emphasis supplied)

- 18. In the said judgement, the Hon'ble Tribunal also relied on the case of The Shipping Corporation of India and M/s Srinivas Transports in para 5.14, which reads as under:
 - "5.14 A similar issue arose for consideration in the case of The Shipping Corporation of India [2013-TIOL-1652-CESTAT-MUM = 2014 (33) S.T.R. 552 (Tri. Mumbai)], In the said case, the appellant therein provided vessels to ONGC on charter hire basis for transportation of crude oil from Bombay High to the refinery onshore. This tribunal held that the service provided would merit classification under SOTG service. In a recent decision in the case of Srinivasa Transports [2014 (34) S.T.R. 765 (Tri.-Bang.)], a question arose as to whether supply of tractor trailers along with trained drivers to undertake transportation of containers within a container terminal would merit classification under SOTG service or as business support service. This tribunal held that the said service merits classification under SOTG service. These decisions also support the view that charter hire of drilling rigs on time charter basis will fall under SOTG service".

The ratio of the above mentioned decisions is squarely applicable to the facts of the present case.



- 19. In view of the foregoing discussions, I hold that the activities carried out by the appellant correctly falls within the ambit of service category of "supply of tangible goods" w.e.f. 16.05.2008, as all the essential ingredients of the taxable service under the said category as defined under Section 65(105)(zzzzj) of the Finance Act, 1994 are fully satisfied.
- 20. Further, the appellant has argued that ONGC has paid service tax on 25% under GTA Service; and therefore this amount cannot be taxed again under the service of "supply of tangible goods". From the foregoing discussion, I observe that during the disputed period,

the liability of paying service tax was on the appellant and not on the service recipient. Hence, for the disputed period, the amount paid by ONGC is not relevant. In the circumstances, the said argument is not tenable.

- In view of the above discussion, the appellant is liable for payment of service tax for the disputed period under the category of taxable service of "Supply of Tangible Goods" as specified under. Section 65(105)(zzzzj) of the Finance Act, 1994 in respect of services rendered to ONGC. As duty was not discharged within stipulated time, interest is payable under section 75 of the Finance Act, 1994.
- 22. I find that the adjudicating authority has imposed penalties under different provisions of the Finance Act. The penalties imposed under the said Sections appear to be apt in the light of the circumstances of the case.
- 23. In this backdrop, I reject the appeal filed by the appellant and uphold the impugned order passed by the adjudicating authority. The appeal stands disposed of accordingly.

Date: 07 /09/2016

(Abhai Kumar Srivastav) Commissioner (Appeals-1) Central Excise, Ahmedabad.

Attested

(Mohanan V.V.)

Superintendent (Appeals-I)

Central Excise, Ahmedabad

<u>R.P.A.D.</u>

To M/s Jay Somnath Transport Co. 1, Gokul Shopping Centre, Malgodown, Mehsana, Gujarat.

Copy to:-

- 1. The Chief Commissioner, Central Excise Zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III
- 3. The Addl./Joint Commissioner, (Systems), Central Excise, Ahmedabad-III
- 4. The Dy. / Asstt. Commissioner, Central Excise, S.T Division, Gandhinagar, Ahmedabad-III
- 5. Guard file.
- 6. P.A.

